

प्रेषक

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 15 फरवरी, 2010

विषय:—नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स के समान दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 10% (दस प्रतिशत) तथा दिनांक 01 जुलाई, 2009 से 9%(नौ प्रतिशत) की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 894/IV-श०वि०-09-03(न०वि०)/02 दिनांक 06 सितम्बर, 2009 के द्वारा नगर निगम, देहरादून के पेंशनर्स को राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनर्स के समान मंहगाई भत्ते का लाभ प्रदान करते हुए 54 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य की गई थी। चूंकि राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-7 के कार्यकाल ज्ञाप संख्या-164/XXVII (7)म०भ०/2009 दिनांक 26 अगस्त, 2009 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मंहगाई राहत की 10 प्रतिशत(दस प्रतिशत) एवं शासनादेश संख्या 299/XXVII (7)म०भ०/2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2009 से मंहगाई राहत की 09प्रतिशत (नौ प्रतिशत) की किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतः उक्त एवं शहरी विकास विभाग के शासनादेश सं० 894/IV-श०वि०-09-03(न०वि०)/02 दिनांक 06 सितम्बर, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मंहगाई राहत की दर 10 प्रतिशत बढ़ाकर अब कुल 64 प्रतिशत तथा दिनांक 01 जुलाई 2009 से मंहगाई राहत की दर 09प्रतिशत बढ़ाकर कुल 73 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने अपुनरीक्षित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन तथा राहत की कुल धनराशि उस धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा अपने उसी श्रेणी के अपुनरीक्षित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन और राहत के रूप में समय समय पर दी जाती है।

3— जिन कर्मचारियों का 1.1.2006 से वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है उन्हें पूर्व से राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति मंहगाई भत्ता देय है। अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स की भांति नगर निगमों के सेवा निवृत्त को मंहगाई राहत अनुमन्य होगी तथा जिन पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षित नहीं हुई है उन्हें पूर्व दरों के आधार पर निर्गत शासनादेश के आधार पर अनुमन्य होगी।

4- उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने अपुनरीक्षित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दी जाने वाली मंहगाई राहत में शासन द्वारा कोई अंशदान/अनुदान देय नहीं होगा तथा उक्त भुगतान निगम द्वारा अपने वित्तीय श्रोतों से किया जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-2807/XXVII(7)/2010, दिनांक 04 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

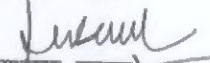
(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 04 /IV(1)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
6. वित्त (वि0आ0-ब्या0नियं0) अनुभाग-7।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड बुक।

ओझा से,


(सुभाष चन्द्र)

अनु सचिव।